पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 1733/2017

=====

अभय चन्द्र चौधरी, पुत्र स्वर्गीय इन्दुकर चौधरी, निवासी ग्राम- चानपुरा, पुरवारी टोल,
थाना-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

श्रीमती शोभा चौधरी उर्फ रुन्नी चौधरी, पत्नी अभय चंद्रा चौधरी, पुत्री श्री चंद्र मोहन
ठाकुर, निवासी ग्राम-भच्छी ठाकुर टोल, थाना+जिला- मधुबनी

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रणजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : कोई नहीं

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125(4) और (5)—हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—
धारा 24—भरण-पोषण—नीचे की अदालत ने याचिकाकर्ता (पति) को भरण-पोषण पेंडेंट
लाइट का भुगतान करने और उत्तरदाता (पत्नी) को मासिक मुकदमे के खर्च का भुगतान
करने का निर्देश दिया—कोड, 1973 की धारा 125 के तहत कोई भरण-पोषण नहीं दिया
गया—उत्तरदाता की भरण-पोषण याचिका डिफॉल्ट और बिना मुकदमा चलाए खारिज
कर दी गई—जब मेरिट पर कोई निर्णय नहीं है, तब अधिनियम, 1955 की धारा 24 के

तहत उत्तरदाता के दावे को अस्वीकार करने के लिए भरण-पोषण मामले के खारिज होने पर जोर देना केवल न्याय का अपमान करेगा—धारा 125, कोड और अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत प्रदान किए गए अधिकार और उपचार की प्रकृति भिन्न है और वसूली की प्रक्रिया और विधि भी भिन्न है और उपचार एक-दूसरे के साथ असंगत नहीं हैं—याचिकाकर्ता ने विवादित आदेश में कोई दोष बताने में असफल रहे—भरण-पोषण कानूनों को सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में स्वतंत्र पत्नी और बच्चों को सहायता प्रदान करने और उन्हें भिक्षाटन और दरिद्रता में गिरने से रोकने के लिए लागू किया गया है—विवादित आदेश में कोई दोष नहीं—संशोधन के साथ पुष्टि की गई—याचिका निस्तारित की गई।

(पैराग्राफ 12, 14, 15, 16)

आपराधिक अपील संख्या 730 2020; 2019 VII AD (दिल्ली) 466: एससीसी ऑनलाइन डेल 9526; (1991) 290 एमएलजे 1; 1985 के.एल.टी 849; (2010) 9 एससीसी 385—निर्भर किया गया ।

2009 एसएससी ऑनलाइन एपी 486: (2010) 1 डीएलएस 545; एआईआर 1996 एससी 333; एआईआर 2002 एससी 33; (2005) 4 एससीसी 74: एआईआर 2005 एससी 592; (2017) 4 एसएससी 2730—संदर्भित किया गया ।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा
सीएवी निर्णय
दिनांक: 18-03-2025

याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए तत्काल सिविल विविध याचिका दायर की गई है:-

“(i) एम.एम. केस संख्या 77/2016 (अनुलग्नक-7) में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी द्वारा पारित दिनांक 2.8.2017 के आदेश को रद्द करना जिसके तहत उन्होंने विपक्षी/प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार किया है और याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से विपक्षी पक्ष को मामले के लंबित रहने के दौरान प्रति माह 3500/- रुपये और 1500/- रुपये भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया है।

(ii) कार्यवाही के व्यय के बजाय केवल रखरखाव का निर्देश देने और रखने के लिए

(iii) किसी अन्य रिट/रिट, आदेश/आदेशों को जारी करने के लिए निर्देश/निर्देश जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार पाया जा सकता है।”

2. अनावश्यक विवरण से हटकर, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(1) (ए) के तहत 11.04.2016 को प्रतिवादी/प्रतिवादी के खिलाफ एम.एम. केस संख्या 77/2016 के तहत वैवाहिक मामला दायर किया है, जिसका कारण प्रतिवादी द्वारा बिना किसी कारण के परित्याग कर दिया जाना है। प्रतिवादी उपस्थित हुआ और याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया। वैवाहिक मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया। 25.04.2017 को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी के समक्ष एम.आर. केस संख्या 82/2017 के तहत याचिकाकर्ता से भरण-पोषण की मांग की गई। इसके बाद, प्रतिवादी ने

16.06.2017 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता ने 16.06.2017 को याचिका पर अपना प्रत्युत्तर दायर किया जिसमें प्रतिवादी के सभी बयानों और दावों को नकार दिया और इस आधार पर याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया कि प्रतिवादी द्वारा दायर भरण-पोषण का मामला लंबित है। विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी ने पक्षों को सुनने के बाद, 16.06.2017 को आवेदन को अनुमति दी और याचिकाकर्ता को 3500/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में और 2500/- रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी को मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 1500/- प्रति माह देने का आदेश दिया। दिनांक 02.08.2017 का उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौतीधीन है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि आरोपित आदेश टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसमें कई कमियाँ हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश तथ्यों और इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में लागू कानून पर विचार किए बिना पारित किया गया है। याचिकाकर्ता की प्रतिवादी पत्नी एक क्रूर महिला है और वह अपने ससुराल को खुद छोड़कर चली गई और उसके बाद अपने दो बच्चों को छोड़कर अपने माता-पिता के घर में खुशी से रह रही है। दोनों बच्चों की देखभाल याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही है। याचिकाकर्ता अपने बच्चों की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने वेतन का आधा हिस्सा खर्च करता है। याचिकाकर्ता एक निजी फर्म में काम करता है और लगभग 15,000 रुपये प्रति माह कमाता है और इस अल्प आय में से उसे अपने साथ-साथ अपने बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। इस प्रकार, इन बच्चों की देनदारियाँ इस याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जा रही हैं न कि

प्रतिवादी द्वारा। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी अपनी गलती का फायदा उठा सकती है। उसने बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है, लेकिन इस तथ्य पर विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने विचार नहीं किया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने पहले ही भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर कर दिया है और उसने अंतरिम भरण-पोषण के लिए भी आवेदन किया है। विद्वान वकील ने बाद के विकास का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर भरण-पोषण का मामला उसी पारिवारिक न्यायालय द्वारा 24.01.2020 को खारिज कर दिया गया है। यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत स्थायी भरण-पोषण के लिए अनुदान की याचिका खारिज कर दिया गया है, इसलिए वैवाहिक मामले की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 22.01.2021 को 02.08.2017 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को भी खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.04.2018 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश द्वारा मूल आदेश को संशोधित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया गया था जबकि मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 1500/- रुपये प्रति माह के भुगतान के आंशिक आदेश पर रोक लगा दी गई है।

4. विद्वान वकील ने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए गए भरण-पोषण की क्षणिक प्रकृति पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है

और वैवाहिक मामले के निपटारे के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में, विद्वान वकील ने *अरविंद चैनजी बनाम कृष्णवेनी* के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का हवाला दिया, जो *2009 एसएससी ऑनलाइन एपी 486: (2010) 1 डीएलएस 545* में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि एक बार कार्यवाही का निपटारा हो जाने के बाद, भरण-पोषण के भुगतान के संबंध में व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। यह आगे माना गया है कि, हालांकि, एक पक्ष, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण दिया गया था, मुख्य कार्यवाही के निपटारे की तारीख से परे इसके भुगतान पर जोर नहीं दे सकता है।

5. विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने परित्याग की तर्कसंगतता की जांच नहीं की, क्योंकि धारा 125 (4) और (5) के तहत भरण-पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति के दावे पर रोक लगा दी जाती है, यदि परित्याग के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि माता-पिता दोनों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की देखभाल करें और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कमा रहा है, प्रतिवादी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि उसका परित्याग न्यायोचित है और जब तक वह ऐसा नहीं करती, वह किसी भी अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद *मेजर अशोक कुमार सिंह बनाम षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, वाराणसी एवं अन्य के मामले में एआईआर 1996 एससी 333* में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता नपुंसक नहीं है और प्रतिवादी पत्नी ने बिना किसी कारण के उसे

छोड़ दिया है, इसलिए वह याचिकाकर्ता से भरण-पोषण मांगने की हकदार नहीं है। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि प्रतिवादी अपीलकर्ता से उसकी नपुंसकता के आधार पर अलग रहने का हकदार है और यदि प्रतिवादी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपीलकर्ता से भरण-पोषण मांगने की हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद **रोशन दीन बनाम प्रीति लाल एआईआर 2002 एससी 33** और **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एवं अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब एवं अन्य, 2005 (4) एससीसी 741 : एआईआर 2005 एससी 592** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो और निर्णयों का हवाला दिया जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों के संबंध में रिपोर्ट की गई और विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त शक्ति न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान की गई है न कि इसे विफल करने के लिए। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण केवल अकादमिक कोण से कानून की किसी त्रुटि को चुनना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या कानून की गलत व्याख्या के कारण अन्याय हुआ है। न्यायालय का प्रयास पूर्ण न्याय करने की ओर होना चाहिए। विद्वान वकील ने **जेटेंदर कुमार उर्फ राजन बनाम कमलेश उर्फ गंगा एवं अन्य, (2017) 4 जेसीसी 2730** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि माता-पिता दोनों का कानूनी, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा और जीवन स्तर प्रदान करें। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश को रद्द किया जाए और वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए।

7. अनेक अवसरों के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने कोई तर्क प्रस्तुत किया, यद्यपि प्रतिवादी की ओर से *वकालतनामा* दाखिल किया गया है।

8. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है। यद्यपि, आरोपित आदेश के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई गई हैं, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा बहुत सीमित दायरे में है और वही यह है कि क्या विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रतिवादी को दिया गया अंतरिम भरण-पोषण संधारणीय है या नहीं? अब, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है:-

“24. कार्यवाही के दौरान भरण-पोषण और व्यय- जहां इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, के पास अपने भरण-पोषण और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, वहां वह पत्नी या पति के आवेदन पर प्रतिवादी को आदेश दे सकता है कि वह याचिकाकर्ता को कार्यवाही के व्यय और कार्यवाही के दौरान मासिक रूप से ऐसी राशि का भुगतान करे, जो याचिकाकर्ता की अपनी आय और प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को उचित लगे।”

9. यह बहुत स्पष्ट है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए जाने वाले भरण-पोषण की प्रकृति अस्थायी है और यह केवल पक्षों के बीच मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पक्ष के पक्ष में यह भरण-पोषण लंबित है, वह उपचारहीन हो जाएगा क्योंकि ऐसा पक्ष स्थायी गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकता है या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर कर सकता है। जहां तक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदन की स्थिरता

के बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के दावे का संबंध है, जबकि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए दावा पहले ही किया जा चुका है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक ओर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का अनुदान और दूसरी ओर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण का अनुदान परस्पर अनन्य नहीं हैं। इस संबंध में *अरविंद चैनजी* (सुप्रा) मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

10. जहां तक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रतिवादी को किसी भी रखरखाव का दावा करने से वंचित करने वाले रखरखाव मामले को खारिज करने के बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के दावे का संबंध है, यह मुद्दा अब अस्तित्व में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *रजनीश बनाम नेहा और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 730/2020)* के मामले में *आरडी बनाम बीडी 2019 VII एडी (दिल्ली) 466: एससीसी ऑनलाइन डेल 9526* के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विधायी जनादेश में विभिन्न कानूनों के तहत पत्नी को रखरखाव प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह विधायिका का इरादा नहीं था कि एक बार रखरखाव की कार्यवाही में से किसी एक में आदेश पारित होने के बाद, आदेश किसी अन्य कार्यवाही में रखरखाव के मुद्दे पर पुनर्विचार को रोक देगा।

11. वर्तमान मामले में, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई भरण-पोषण नहीं दिया गया है और विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी के दिनांक 24.01.2020 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी की भरण-पोषण याचिका को चूक और गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। जब

गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं होता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार करने के लिए भरण-पोषण मामले को खारिज करने पर जोर केवल न्याय से इनकार करने का कारण होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनेश (सुप्रा)** के मामले में, विभिन्न कानूनों के तहत भरण-पोषण के दावे पर विचार करते हुए, निम्न प्रकार से निर्णय दिया:-

“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक पत्नी विभिन्न कानूनों के तहत भरण-पोषण के लिए दावा कर सकती है। उदाहरण के लिए, डी.वी. अधिनियम और सीआरपीसी की धारा 125 या एच.एम.ए. के तहत भरण-पोषण मांगने पर कोई रोक नहीं है। हालाँकि, पति को प्रत्येक कार्यवाही के तहत भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देना अनुचित होगा, जो पिछली कार्यवाही में दी गई राहत से स्वतंत्र है। यदि पत्नी को पहले से शुरू की गई कार्यवाही में भरण-पोषण दिया जाता है, तो वह भरण-पोषण के लिए बाद की कार्यवाही में इसका खुलासा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, जिसे किसी अन्य अधिनियम के तहत दायर किया जा सकता है। बाद की कार्यवाही में भरण-पोषण की मात्रा तय करते समय, सिविल कोर्ट/पारिवारिक कोर्ट किसी भी कार्यवाही में दिए गए भरण-पोषण को ध्यान में रखेगा और दावेदार को देय भरण-पोषण का निर्धारण करेगा।

12. इसलिए इस बिंदु पर भी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क संधारणीय नहीं है। इसी तरह का दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **मनोज वनजा बनाम गोपू** के मामले में लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट **(1991) 290 एमएलजे 1** में की गई थी, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने **कुट्टप्पन बनाम थंका 1985 के.एल.टी. 849** के मामले का संदर्भ देते हुए कहा था कि धारा 125, सीआरपीसी और हिंदू विवाह

अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए गए अधिकार और उपाय का उद्देश्य, प्रकृति अलग-अलग है और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया और विधि भी अलग-अलग हैं और उपचार एक-दूसरे के साथ असंगत नहीं हैं।

13. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क से कोई विवाद नहीं हो सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्याय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है। इस न्यायालय को अपने क्षेत्र में सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण के लिए शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है और उक्त शक्ति न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनकी सीमाओं के भीतर रखने और यह देखने के लिए है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से आगे न बढ़ें और इस शक्ति का बहुत संयम से और न्याय के कारण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, न कि इसे विफल करने के लिए। अपनी अधीक्षण शक्ति के तहत, यह न्यायालय तथ्यों के विवादित प्रश्न पर गौर नहीं करेगा या ट्रायल कोर्ट से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा। यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इसके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में केवल गलत आदेशों में भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *जय सिंह एवं अन्य बनाम एम.सी.डी. एवं अन्य के मामले में (2010) 9 एस.सी.सी. 385* में रिपोर्ट की कि उच्च न्यायालय "चीनी दुकान में बैल" की तरह काम नहीं कर सकते हैं और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त बाधाओं के भीतर होना चाहिए। जब तक रिकॉर्ड में कोई विकृति स्पष्ट न हो या अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि न हो जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, यह न्यायालय विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित

किसी भी अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा। इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रतिवादी पत्नी के बिना किसी वैध और उचित आधार के परित्याग के संबंध में उठाए गए तर्क तथ्यों की सराहना की मांग करते हैं और यह एक ऐसा मामला है जिस पर विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है और यह न्यायालय इस स्तर पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता है।

14. यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन वे इस न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं दिखा पाए हैं कि आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, सिवाय इस तथ्य के कि बच्चे याचिकाकर्ता के साथ रह रहे हैं और उसे बच्चों की जरूरतों का भी ध्यान रखना है। चूंकि यह मुद्दा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा इस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा मासिक आधार पर मुकदमेबाजी व्यय के अनुदान के संबंध में है, जिसमें कुछ योग्यता है क्योंकि विवादित आदेश को इस पहलू पर बोलने वाला आदेश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है और विवादित आदेश के इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य तर्क और प्राधिकारी वर्तमान याचिका के निपटान के उद्देश्य से अधिक प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, आरोपित आदेश एक लंबित आदेश है और वैवाहिक मामले का निपटान करने के लिए

पक्षों का प्रयास होना चाहिए और रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि वैवाहिक मामला वर्तमान प्रतिवादी के साक्ष्य के चरण में आगे बढ़ रहा है। एक बार वैवाहिक मामले का निपटारा हो जाने के बाद, अंतरिम आदेश समाप्त हो जाएगा और इसलिए, अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अपने मामले को आगे बढ़ाने के बजाय, याचिकाकर्ता को अपने वैवाहिक मामले को पूरी लगन से चलाने की सलाह दी जाएगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि भरण-पोषण कानून सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में आश्रित पत्नी और बच्चों को सहायता प्रदान करने और उन्हें आवारागर्दी और अभाव में पड़ने से रोकने के लिए बनाए गए हैं।

16. अतः पूर्व में की गई चर्चा के आलोक में मेरा यह विचार है कि तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात पारित किए गए विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा इसे थोड़े संशोधन के साथ पुष्ट किया जाता है कि मासिक आधार पर दिए जाने वाले मुकदमेबाजी खर्च को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 77/2016 के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित होने के कानूनी व्यय का आकलन करने के पश्चात नए सिरे से आदेश पारित करके संशोधित किया जाएगा।

17. तदनुसार, वर्तमान याचिका उपरोक्त निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है।

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैवाहिक वाद वर्ष 2016 में संस्थित किया गया है, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन दिए बिना इसके शीघ्र निस्तारित करने के लिए कदम उठाएंगे।

19. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

बालमुकुंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।